भीतर पूर्ण साक्षरता के लिये क्षेत्र आधारित दृष्टिकोण अपनाया जाय और परियोजनाओं के आकार को छोटा बनाया जाय ताकि उन पर प्रभावी ढंग से निगाह रखी जा सके और पर्यवेक्षण किया जा सके, उन्हें लागत प्रभावी तथा परिणामोन्मुखी बनाया जा सके । चालू वित्तीय वर्ष से संशोधित परियोजना कार्यान्वित की जा रही है ।

पेट्रोल की बचत के संबंध में हिदायतें

*28. **डा० रत्नाकर पाण्डेय** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी वाहनों से पेट्रोल की खपत और बचत के संबंध में विभिन्न सरकारी विभागों को क्या दिशा-निर्देश जारी किये गये है; और

(ख) उनका क्या परिणाम निकला है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शान्ताराम पोटदुखे) : (क) और (ख) एक विवरण-पत्र सभा पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

(क) सरकारी वाहनों में पेट्रोल/डीजल की खपत तथा उसमें बचत किये जाने के बारे में निम्नलिखित मार्ग-निर्देश जारी किये गये हैं:-

(i) सभी मंत्रालयों/विभागों को जून, 1990 में अनुदेश जारी किये गये थे कि 1990-91 से आगे, स्टाफ कारों सहित सरकारी वाहनों में पेट्रोल और डीजल की खपत में 1989-90 के दौरान की पेट्रोल और डीजल की खपत से 20% की कमी की जाय । इन अनुदेशों को अप्रैल, 1991 में दोहराया गया था । हाल ही की पेट्रोल की मूल्य वृद्धि के बाद, सभी मंत्रालयों/विभागों को 1-8-1991 को और अनुदेश जारी कर दिये गये थे कि 1991-92 के दौरान पेट्रोल/डीजल पर होने वाले व्यय को 1989-90 के दौरान के पेट्रोल/डीजल की उस मात्रा पर होने वाले व्यय तक सीमित कर दिया जायेगा जो 1989-90 के दौरान पेट्रोल/डीजल की खपत पर 20% की कटौती करके नियत किया गया था ।

(ii) 22 अगस्त, 1990 को अनुदेश जारी किये गये थे कि सरकारी वाहनों को, ऐसी स्थिति को छोड़कर जबकि उन्हें आपत्काल तथा अन्य अपरिहार्य प्रचालनात्मक ड्यूटियों पर लगाया गया हो, और स्टाफ कारों को रविवारों को इस्तेमाल नहीं किया जायेगा ।

(iii) पूलिंग व्यवस्था पर पुनः जोर देते हुये जनवरी, 1991 में सभी मंत्रालयों विभागों को अनुदेश जारी किये गये थे कि अधिकारी कार्यालय और निवास के बीच की तथा बैठकों में शामिल होने के लिये यात्राओं के दौरान अलग-अलग कारों में यात्रा करने के बजाय जहां तक संभव हो एक ही कार में यात्रा करें ।

(ख) मंत्रालयों/विभागों को सरकारी वाहनों द्वारा पेट्रोल/डीजल की खपत के बारे में सूचना निर्धारित फार्मेट में भेजनी अपेक्षित है ? 24 सरकारी विभागों में प्राप्त पूर्ण सूचना पेट्रोल के संबंध में

1989-90 की तुलना में 1990-91 के दौरान 14.08% की बचत दिखाती है । हाई स्पीड डीजल के बारे में 8 विभागों से प्राप्त पूर्ण सूचना 1989-90 की तुलना में 1990-91 के दौरान 33.63% बचत दिखाती है ।

Establishment of a Lung Institute at Bhopal

*29. SHRI SURESH PACHOURI: Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Government of Madhya Pradesh had long ago requested the Central Government to establish a Lung Institute for the victims of Bhopal Gas Leak Disaster in the State capital;

(b) if so, what action the Central Government have taken in the matter; and

(c) by when Government propose to establish the said Institute at Bhopal?

THE MINISTER OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI M. L. FOTEDAR): (a) to (c) A statement is laid on the Table of the House.

Statement

Though no formal proposal has been received for the establishment of a Lung Institute for the victims of Bhopal Gas Leak Disaster, the Government is concerned over the issue of industrial accidents which can claim many lives and cause disability to many others. Accordingly, the Indian Council of Medical Research (ICMR) have formulated a proposal for the establishment of National Lung Institute for Industrial Disaster at Delhi with three satellite regional Centres at Bhopal, Ahmedabad and Pune. No decision has yet been taken on this proposal.

Literacy rate in the Country

*30. SHRI RAMDAS AGARWAL: Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) what is the present rate of literacy in the country, State-wise; and

(b) what steps Government have taken so far to increase the percentage of literacy, indicating the expenditure incurred on this account in the country during the last three years upto 31st March, 1991, yearwise and State-wise?

THE MINISTER OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (SHRI ARJUN SINGH): (a) and (b) A statement is laid on the Table of the Sabha.

Statement

(a) According to the provisional figures of the 1991 census, the literacy rate in the country for population aged 7 years and above was 52.11 per cent. Details showing the State-wise literacy rate are given at Statement-I.

(b) Universalisation of the elementary education including the programme of non-formal education for school drop-outs, and the National Literacy Mission which aims at imparting functional literacy to 80 million adult illiterates in the 15-35 age-group by 1995 form an integral part of the larger programme for eradication of illiteracy in the country.

Details showing the amount of grant released by the Central Government to the State Governments, UT Administrations and various agencies engaged in promotion of adult education and elementary education in these States/UTs during the last three years are given at Statement II and III. In addition, th